श्री नारकेसरी प्रकाशन लिमिटेड और अन्य

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि

15 अक्टूबर, 1984

[ए. पी. सेन और ई. एस. वेंकटरमैया, न्यायाधिपतिगण]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, धारा 2(9)- प्रशासनिक कर्मचारियों के सदस्य और प्रिंटिंग प्रेस के संपादकीय कर्मचारी- चाहे "कर्मचारी"

शब्द और वाक्यांश: 'कर्मचारी'-'किसी भी वेतन पर नियोजित कोई भी व्यक्ति। कारखाने के प्रशासन से सम्बंधित कार्य- का अर्थ. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, धारा 2(9);

क़ानून की व्याख्या- किसी अधिनियम के प्रावधानों को दूसरे अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कब नियंत्रित किया जा सकता है?

अपील में अपीलकर्ता समाचार पत्रों के मुद्रक और प्रकाशक थे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने 1 अक्टूबर, 1975 को अपीलकर्ताओं को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 28 जनवरी, 1968 से समाचार-पत्रों के प्रशासनिक और संपादकीय कर्मचारियों के संबंध में योगदान देने के लिए कहा गया। आधार यह है कि उपरोक्त

कर्मचारी 1966 के संशोधन अधिनियम संख्या 44 द्वारा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2(9) में अभिव्यक्ति 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त मांगें किए जाने के बाद, अपीलकर्ताओं 28 जनवरी, 1968 और 19 नवंबर, 1976 के बीच की अवधि के दौरान उक्त कर्मचारियों के संबंध में योगदान करने के दायित्व पर सवाल उठाने वाले अधिनियम की धारा 75 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के समक्ष आवेदन ने दायर किया। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में अपने दायित्व पर विवाद नहीं किया। 19 नवंबर 1976 के बाद की अवधि, जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा धारा 1 (5) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इन आवेदनों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विरोध किया गया था।

कर्मचारी बीमा न्यायालय ने आवेदनों को यह कहते हुए अनुमति दी कि जब तक राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 1(5) के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक यह अधिनियम अपीलकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा यानि कि प्रेस के प्रशासनिक और संपादकीय अनुभागों में, उक्त कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 2(9) द्वारा परिभाषित 'कर्मचारी' नहीं माना जा सकता है।

इसके बाद निगम ने अधिनियम की धारा 32 के तहत उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील दायर की, जिसे यह मानते हुए स्वीकार कर

लिया गया कि संबंधित कर्मचारी धारा 2(9) में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आते हैं; इसलिए अपीलकर्ता अधिनियम के तहत उनके संबंध में भी प्रासंगिक अवधि के दौरान योगदान करने के लिए उत्तरदायी थे।

इस न्यायालय में अपीलों को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों की जांच से पता चलता है कि प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस के प्रशासनिक अनुभाग और संपादकीय अनुभाग में वेतन के लिए नियोजित व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(9) में परिभाषित कर्मचारी हैं और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की गई मांग जायज है। [970 ई]

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का उद्देश्य बीमारी, मातृत्व और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करना और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना है। अधिनियम की धारा 1(4) में प्रावधान है कि यह सबसे पहले मौसमी कारखानों के अलावा सभी कारखानों (सरकार से संबंधित कारखानों सहित) पर लागू होगा। हालाँकि, अधिनियम की धारा 1(5) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और जहां उपयुक्त सरकार एक राज्य सरकार है, छह महीने का नोटिस देने के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी लेगी। ऐसा करने के अपने इरादे से, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों या उनमें से

किसी को किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा तक विस्तारित करें। हालाँकि, अभिव्यक्ति 'स्थापना' को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया था। [967 ए-ई]

3. अधिनियम की धारा 2(9) 'कर्मचारी' शब्द को परिभाषित करती है जिसका अर्थ किसी कारखाने में मजदूरी के लिए नियोजित कोई व्यक्ति या किसी कारखाने के काम के संबंध में मजदूरी के लिए नियोजित कोई व्यक्ति है। इसका मतलब किसी ऐसे प्रतिष्ठान में या उसके काम के संबंध में मजदूरी के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति है जिस पर अधिनियम लागू होता है। [967 एच]

वर्तमान मामलों में, प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस में प्रशासनिक स्टाफ और संपादकीय स्टाफ के सदस्यों को धारा 2(9) के तहत कर्मचारी माना जाना चाहिए। उन्हें संबंधित प्रबंधन द्वारा आकस्मिक या प्रारंभिक या कारखाने के काम से जुड़े काम पर सीधे नियोजित किया जाता है। प्रत्येक मामले में कारखाने का काम समाचार पत्र की छपाई और प्रकाशन है, इसका काम संपादकीय कर्मचारियों के सदस्यों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है जो समाचार पत्र की छपाई के लिए सामग्री तैयार करने में लगे हुए हैं और प्रशासनिक कर्मचारी जो कारखाने के मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। [969 सी-डी]

हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम कर्मचारी बीमा न्यायालय और अन्य, [1978] 2 एस.सी.आर. 345, रॉयल टॉकीज़, हैदराबाद और अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, [1979] 1 एस.सी.आर. 80 और नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी, राज्य बीमा निगम आदि, [1967] 3 एस.सी.आर. 92, संदर्भित किया गया।

4. संपादकीय स्टाफ के सदस्य स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2(9) के खंड (i) के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी उस खंड के अंतर्गत आते हैं जिसमें 'कारखाने के प्रशासन से जुड़े किसी भी काम पर मजदूरी के लिए नियोजित किसी भी व्यक्ति को शामिल करें' शब्द शामिल हैं। [969 एच:970 ए]

5. किसी अधिनियम के प्रभाव को दूसरे अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि एक के प्रावधान दूसरे के प्रावधानों पर असर न डालें। [970 डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3296-67/1984

उच्च न्यायालय, बॉम्बे के एफ.ए. संख्या 35 /1978 और 139/1973 में निर्णय और आदेश दिनांकित 23 जनवरी, 1981 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

बी.कांता राव और विजय फड़के, अपीलकर्ताओं की ओर से।

अब्दुल खादर और आर.एन. पोद्दार, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय वेंकटरामियन, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

श्री नवकेसरी प्रकाशन लिमिटेड और नव समाज लिमिटेड, नागपुर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति द्वारा उपरोक्त दो अपीलों में अपीलकर्ता हैं। अपीलकर्ता क्रमशः 'तरुण भारत' और 'नागपुर टाइम्स' नामक समाचार पत्रों के मुद्रक और प्रकाशक हैं। उनका मामला यह है कि उनके संबंधित संस्थानों के प्रशासनिक और संपादकीय अनुभागों में वेतन के लिए काम करने वाले कर्मचारी 'कर्मचारी' नहीं थे जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 2 (9) में परिभाषित किया गया है, 19 नवंबर, 1976 से पहले किस तारीख को अधिनियम की धारा 1 के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अधिनियम को उक्त कर्मचारी पर भी लागू किया था और इसलिए वे उस तिथि तक कर्मचारियों के संबंध में अधिनियम के तहत कोई योगदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। हालाँकि, वे उस अवधि के दौरान अपने प्रिंटिंग प्रेसों में मजदूरी के लिए नियोजित व्यक्तियों के संबंध में योगदान देने के अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं।

प्रशासनिक और संपादकीय कर्मचारियों के सदस्यों के संबंध में अधिनियम के तहत योगदान करने के लिए अपीलकर्ताओं के दायित्व के

संबंध में विवाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक क्षेत्रीय निदेशक द्वारा 1 अक्टूबर 1975 को जारी नोटिस द्वारा उन्हें बुलाने पर उत्पन्न हुआ, उक्त सदस्यों के संबंध में योगदान करने के लिए जनवरी, 28,1968 से प्रभावी, जिस तारीख को संशोधित अधिनियम संख्या 44/1966 के अनुसार अधिनियम की धारा 2 (9) में 'कर्मचारी' शब्द की संशोधित परिभाषा को संशोधित किया गया है, प्रभाव में आया। उपरोक्त मांगें किए जाने के बाद, अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 75 के तहत कर्मचारी बीमा न्यायालय, नागपुर के समक्ष आवेदन, 28 जनवरी, 1968 और 19 नवंबर, 1976 के बीच की अवधि के दौरान उनके प्रेस के प्रशासनिक और संपादकीय अनुभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में योगदान देने के उनके दायित्व पर सवाल उठाते हुये दायर किया। हालाँकि, उन्होंने 19 नवंबर, 1976 के बाद की अवधि के संबंध में अपने दायित्व पर विवाद नहीं किया, जिस तारीख को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 1(5) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आवेदनों का विरोध किया गया। कर्मचारी बीमा न्यायालय ने आवेदनों को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि जब तक राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा (5) के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक यह अधिनियम अपीलकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। उनके प्रेस के प्रशासनिक और संपादकीय अनुभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 2(9) द्वारा परिभाषित 'कर्मचारी' नहीं

माना जा सकता है। कर्मचारी बीमा न्यायालय के फैसले से दुखी होकर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अधिनियम की धारा 82 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि संबंधित कर्मचारी अधिनियम की धारा 2 (9) में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए अपीलकर्ता अधिनियम के तहत उनके संबंध में प्रासंगिक अवधि के दौरान योगदान करने के लिए उत्तरदायी थे। अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की हैं।

अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटने से पहले, यह बताना होगा कि प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस के प्रशासनिक कर्मचारियों और संपादकीय कर्मचारियों के सदस्यों को मुद्रण और इसके द्वारा निकाला गया समाचार पत्र के प्रकाशन के व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से संबंधित प्रबंधन द्वारा नियोजित किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आशय से दर्ज किए गए इस तथ्य के निष्कर्ष की सत्यता पर हमारे सामने सवाल नहीं उठाया गया है। हालांकि अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि चूंकि प्रासंगिक अवधि के दौरान उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस के फैक्ट्री अनुभागों और स्थापना अनुभागों के बीच अंतर बनाए रखा था, जिसमें उनके प्रेस के प्रशासनिक और संपादकीय अनुभाग शामिल थे, इसलिए कर्मचारी इसमें शामिल थे। स्थापना अनुभागों को उन कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जा सकता है जिन पर अधिनियम लागू था जब तक कि अधिनियम की धारा

1 (5) के तहत जारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से उक्त स्थापना अनुभागों को भी अधिनियम के दायरे में नहीं लाती।

अधिनियम की धारा 2 (9) जो प्रश्नाधीन अवधि के दौरान 'कर्मचारी' शब्द को परिभाषित करती है, इस प्रकार पढ़ें:

> "2(9)" कर्मचारी" का अर्थ है किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में मजदूरी के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और-
>
> (i) जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा कारखाने या प्रतिष्ठान के किसी भी काम पर, या उसके आकस्मिक या प्रारंभिक या उससे जुड़े काम पर सीधे नियोजित किया गया हो, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या प्रतिष्ठान में या कहीं और किया गया हो; या
>
> (ii) जो कारखाने या प्रतिष्ठान के परिसर में या प्रमुख नियोक्ता या उसके एजेंट की देखरेख में किसी तत्काल नियोक्ता द्वारा या उसके माध्यम से ऐसे काम पर नियोजित किया जाता है जो आमतौर पर कारखाने या प्रतिष्ठान के काम का हिस्सा होता है या जो कारखाने या

प्रतिष्ठान के प्रयोजन के लिए किया गया प्रारंभिक होता है या उसके आनुषंगिक कार्य; या

(iii) जिनकी सेवाएँ उस व्यक्ति द्वारा मुख्य नियोक्ता को अस्थायी रूप से उधार दी गई हैं या किराए पर दी गई हैं, जिसके साथ जिस व्यक्ति की सेवाएँ इस प्रकार उधार दी गई हैं या किराए पर दी गई हैं, उसने सेवा का अनुबंध किया है; और इसमें कारखाने या प्रतिष्ठान या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन से जुड़े किसी भी काम पर या कारखाने या प्रतिष्ठान के लिए ज़ॉ सामग्री की खरीद, या उत्पादों के वितरण या बिक्री से जुड़े किसी भी काम पर मजदूरी के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति शामिल है; लेकिन इसमें शामिल नहीं है-

(ए) भारतीय नौसेना, सेना या वायु सेना का कोई भी सदस्य; या

(बी) इस प्रकार नियोजित कोई भी व्यक्ति जिसकी मजदूरी ओवरटाइम काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर पांच सौ रुपये प्रति माह से अधिक है:

बशर्ते कि एक कर्मचारी जिसका वेतन ओवरटाइम काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर, अंशदान अवधि की शुरुआत से

पहले या बाद में किसी भी समय पांच सौ रुपये प्रति माह से अधिक हो, वह उस अवधि के अंत तक कर्मचारी बना रहेगा।"

अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और रोजगार चोट के मामले में कुछ लाभ प्रदान करना है और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना। अधिनियम की धारा 1(4) में प्रावधान है कि यह, सबसे पहले, मौसमी कारखानों के अलावा सभी कारखानों (सरकार से संबंधित कारखानों सहित) पर लागू होगा। अधिनियम की धारा 2 (12) द्वारा 'कारखाना' शब्द को उसके परिसर सहित किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन मजदूरी के लिए नियोजित किए गए थे और जिसके किसी भी हिस्से में विनिर्माण प्रक्रिया बिजली की सहायता से चल रही है या आमतौर पर चल रही है, लेकिन इसमें खान अधिनियम, 1952 के संचालन के अधीन कोई खदान या रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह स्वीकार किया गया है कि प्रबंधन के स्वामित्व वाले प्रिंटिंग प्रेस जहां समाचार पत्र मुद्रित और प्रकाशित होते हैं, कारखाने हैं और अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 1 (5) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और जहाँ उपयुक्त सरकार एक राज्य सरकार है, उसे छह महीने का नोटिस देने के

बाद केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा करने का इरादा, अधिनियम या उनमें से किसी के प्रावधानों को किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा तक विस्तारित करना। अधिनियम में 'स्थापना' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह कोई भी औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या कोई अन्य प्रतिष्ठान हो सकता है जहां कर्मचारी प्रतिष्ठान के व्यवसाय के संबंध में लगे हुए हैं। अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उन कारखानों या प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों का, जिन पर अधिनियम लागू होता है, अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से बीमा किया जाएगा। अधिनियम की धारा 39 में कहा गया है कि इसके तहत देय योगदान में नियोक्ता द्वारा देय योगदान और कर्मचारी द्वारा देय योगदान शामिल होगा। योगदान का भुगतान अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर किया जाना है, सिवाय इसके कि जहां संबंधित कर्मचारियों को अधिनियम के तहत कुछ लाभों से बाहर रखा गया है, उस स्थिति में निगम योगदान की दरें तय करने के लिए अधिकृत है।

अब अधिनियम की धारा 2 (9) पर लौटते हुए यह देखा गया है कि 'कर्मचारी' शब्द का अर्थ किसी कारखाने में मजदूरी के लिए नियोजित कोई व्यक्ति या किसी कारखाने के काम के संबंध में मजदूरी के लिए नियोजित कोई व्यक्ति है, इसका मतलब किसी भी प्रतिष्ठान में या उसके संबंध में

मजूदरी के लिये नियोजित कोई भी व्यक्ति हे, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है। यदि इन मामलों में यह माना जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस के प्रशासनिक या संपादकीय अनुभागों के कर्मचारियों को प्रिंटिंग प्रेस के काम के सिलसिले में नियोजित किया जाता है, जो कि स्वीकृत रूप से कारखाने हैं, तो उन्हें धारा 2 (9) के तहत कर्मचारी माना जाना चाहिए। भले ही अधिनियम की धारा 1(5) के तहत उन धाराओं पर अधिनियम लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तथ्य यह है कि इस तरह की अधिसूचना या तो अत्यधिक सावधानी के रूप में या धारा 2 (9) में परिभाषा के वास्तविक निहितार्थ की गलत समझ पर जारी की गई है, अप्रासंगिक हो जाती है। अपीलकर्ताओं के प्रशासनिक और संपादकीय स्टाफ के सदस्य निस्संदेह प्रिंटिंग प्रेस में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे प्रिंटिंग प्रेस के काम के संबंध में काम नहीं कर रहे हैं जो अधिनियम की धारा 2 (12) के तहत कारखाने हैं।

रॉयल टॉकीज़, आयड्राबो और अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कैंटीन और सिनेमा थिएटर से जुड़े साइकिल स्टैंड पर काम करने वाले कर्मचारियों को सिनेमा थिएटर के काम के सिलसिले में नियोजित व्यक्ति माना गया। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि केवल किसी कारखाने या किसी प्रतिष्ठान के काम के सिलसिले में नियोजित होने से कोई व्यक्ति कर्मचारी होने का हकदार नहीं हो जाता है, लेकिन यह साबित होना चाहिए कि वह केवल काम के सिलसिले में प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं

था। लेकिन अधिनियम की धारा 2 (9) में उल्लिखित तीन श्रेणियों में से एक या अन्य में नियोजित भी दिखाया जाएगा।

इस स्तर पर, इस न्यायालय के दो निर्णयों पर विचार करना आवश्यक है। हैदराबाद एब्ससेट्स सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम कर्मचारी बीमा न्यायालय और अन्य में अपीलकर्ता कंपनी, जिसकी सनतनगर में एक फैक्ट्री थी, जहां वह एस्बेस्टस शीट का निर्माण कर रही थी, ने तर्क दिया कि उसके विभिन्न स्थानों पर स्थित जोनल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, जो सनतनगर में निर्मित उत्पादो की बिक्री के लिये प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे, अधिनियम की धारा 2 (9) की परिभाषा के तहत कर्मचारी नहीं थे क्योंकि जोनल कार्यालय प्रतिष्ठान थे न कि कारखाने। उपरोक्त तर्क को नकारते हुए, इस न्यायालय ने माना कि कच्चे माल की खरीद या कारखाने के उत्पादों के वितरण या या कारखाने के उत्पादों के वितरण या बिक्री के लिए या कारखाने के प्रशासनिक प्रयोजन के लिए कारखाने के कर्मचारी के संबंध में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था और इसलिए अधिनियम की धारा 2 (9) द्वारा परिभाषित एक कर्मचारी था। निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय ने 1966 के अधिनियम संख्या 44 द्वारा अधिनियम की धारा 2 (9) के संशोधन पर भी भरोसा किया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 'कर्मचारी' शब्द में ' कारखाना' प्रशासन से जुड़े किसी भी काम पर मजदूरी के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति' शामिल है।

जब वर्तमान अपीलों पर उपरोक्त निर्णयों के आलोक में विचार किया जाता है, तो प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस में प्रशासनिक कर्मचारियों और संपादकीय कर्मचारियों के सदस्यों को अधिनियम की धारा 2(9) के तहत कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए। इन व्यक्तियों को संबंधित प्रबंधन द्वारा आकस्मिक या प्रारंभिक या कारखाने के काम से जुड़े काम पर सीधे नियोजित किया जाता है। प्रत्येक मामले में कारखाने का काम एक अखबार की छपाई और प्रकाशन है, इसका काम संपादकीय कर्मचारियों के सदस्यों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है जो अखबार की छपाई के लिए सामग्री तैयार करने में लगे हुए हैं और प्रशासनिक कर्मचारी हैं जो कि कारखाने के मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि संपादकीय स्टाफ के सदस्य उस परिसर में लगभग चौबीसों घंटे काम करते हैं जहां प्रिंटिंग प्रेस स्थित है या उसके परिसर में। उनका मुख्य काम प्रेस में आने वाली सूचनाओं के ढेर में से समाचार महत्व वाले संदेशों को चुनना और उन्हें छांटना और समाचार पत्र के माध्यम से संचार के लिए उपयुक्त बनाना है। भले ही वे वास्तव में मुद्रण मशीनों के संचालन में संलग्न न हों, समाचार पत्र की छपाई के लिए 'हड़ताल आदेश' दिए जाने तक मौके पर उनकी उपस्थिति आवश्यक है। ऐसे मामले हैं जहां मुद्रित होने वाली सामग्री में परिवर्तन मुद्रण प्रक्रिया शुरू होने से कुछ मिनट पहले भी किया जाता है और ऐसे मामले भी होते हैं जहां समाचार पत्र की कुछ प्रतियां मुद्रित होने के बाद भी, उन्हें किसी जिम्मेदार की सलाह पर अंतिम

मिनट में रोक दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। संपादकीय स्टाफ के सदस्य अज्ञात नहीं हैं। संपादक, समाचार संपादक, उप-संपादक, रिपोर्टर आदि जो प्रेस में संपादकीय स्टाफ का गठन करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से समाचार के द्वारपाल के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे यह निर्धारित करते हैं कि क्या प्रकाशित किया जाना चाहिए और क्या प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने के उद्देश्य से स्थापित एक प्रिंटिंग प्रेस संपादकीय कर्मचारियों के सदस्यों की सेवाओं को लगभग तब तक उपलब्ध कराए बिना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि समाचार पत्र प्रिंटिंग मशीन से बाहर न आ जाए। वे वस्तुत: समाचार पत्र प्रेस का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें मुद्रण प्रेस कार्य के सिलसिले में नियोजित किया जाता है। संपादकीय स्टाफ के सदस्य स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 2(9) के खंड (1) के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों के मामले में भी ऐसा ही है। वे उस खंड के अंतर्गत आते हैं जिसमें ये शब्द शामिल हैं कि "कारखाने" के प्रशासन से जुड़े किसी भी काम पर मजदूरी के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति शामिल है, यहां यह कहा जा सकता है कि 1966 के अधिनियम संख्या 44 द्वारा किए गए संशोधन के बिना भी इस न्यायालय में नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि (यह विचार किया गया था कि किसी कारखाने के लिपिक कर्मचारी आदि चाहे वे कारखाने के भीतर या बाहर काम करते हों" अधिनियम की

धारा 2 (9) के तहत कर्मचारी होंगे, जैसा कि यह अपने संशोधन से पहले था।

तर्क यह है कि चूंकि मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत व्यक्ति को श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 2(9) के तहत श्रमजीवी पत्रकार नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसमें कार्यरत सदस्य प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यह एक अत्यंत उदार तर्क है और इस पर आगे जांच करने लायक नहीं है। अधिनियम पर प्रभाव को किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जब तक कि एक के प्रावधानों का दूसरे के प्रावधानों पर प्रभाव न पड़े। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं है। तर्क यह है कि चूंकि यह अधिनियम वर्किंग जर्नलिस्ट (सेवा की शर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 द्वारा समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इसने धारा 3, 14 और 15 द्वारा कुछ कानूनों को लागू किया है, इसलिए अधिनियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए। संपादकीय कर्मचारियों पर लागू आवेदन का भी कोई औचित्य नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि अधिनियम की धारा 2(9) स्पष्ट रूप से उन्हें अधिनियम के दायरे में लाती है।

अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने पर, हमारा विचार है कि प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस के प्रशासनिक अनुभाग और संपादकीय अनुभाग में मजदूरी के लिए नियोजित व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(9) में परिभाषित कर्मचारी हैं और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की गई मांग जायज है,

परिणामस्वरूप अपीलें विफल होती हैं और उन्हें जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

एन.वी.के.

अपीलें खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।